all pages:20 JAN Page 1.qxd 6/30/2023 2:46 AM Page 1

राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI-UPHIN/2014/58463

द संडे व्यूज़

www.thesundayviews.com, www.indiaexpressnews.com twitter.com/sundayviews

लखनऊ से प्रकाशित

वर्ष : 9 अंक : 51 लखनऊ, रविवार, 25 जून, 2023 पृष्ठ : 08 मूल्य : 3/-

सचिवालयः चिराग तले अंधेरा

मुख्यमंत्री के ट्रांसफर पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रमुख सचिव!

संजय पुरबिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तबादला नीति का शासन में बैठे बड़े अधिकारी ही मजाक बना रहे हैं। अधिकारी नहीं चाहते कि उनके चहेतों की कुर्सी पर कोई और आकर बैठे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की नीति पर अधिकारियों के खास भारी पड़ रहे हैं। बात प्रदेश के कोने में पड़ने वाले जनपद की नहीं बल्कि सचिवालय प्रशासन की कर रहे हैं क्योंकि यहीं से सभी विभागों के समीक्षा अधिकारी,अनुभाग अधिकारी,अनु-सचिव,उप-सचिव,संयुक्त सचिव के पदों के तबादले विभिन्न विभागों में होते हैं। सचिवालय प्रशासन में तैनात संयुक्त सचिव- अजय पाण्डेय,जय प्रकाश पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी- किशलय सिंह, अनु सचिव- जयशंकर,अनु सचिव - गीता राठौर भी अपने-अपने पदों पर गत चार से पांच वर्ष से तैनात हैं जो कि सचिवालय प्रशासन नीति के विपरित है। सवाल यह है कि जब सचिवालय प्रशासन में जहां मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार बैठती है,वहीं पर तबादला नीति का दम घोंटा जा रहा है तो प्रदेश भर में सभी विभागों पर कैसे नकेल कैसे नकेल कसा जायेगा? क्या लंबे समय से एक ही जगह पर जमे समीक्षा अधिकारी,संयुक्त सचिव,सचिव व अनु सचिव भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? सरकार का ही कहना है कि नियमावली के तहत सभी वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को तबादला किया जाये ताकि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो और जीरो टॉलरेंस पर पूरी तरह से काम हो...।

शेष भाग पेज 7 पर

पीसीएस ज्योति मौर्या ...
देखें पेज 03

मलिहाबाद विधान सभा...
देखें पेज 06

लखनऊ कन्ट्रक्शन का...
देखें पेज 08

चुटकी बजाकर फरियादियों को फैसला सुनाती हैं विधायक जय देवी

मलिहाबाद विधान सभा का एक-एक सदस्य मेरे परिवार का हिस्सा है : जय देवी

दिव्या श्री.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने साबित कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सकारात्मक सोच की वजह से ही महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। यही वजह है कि राजनीति में आने वाली महिलायें जमीनी स्तर से जुड़कर अपने संस्कार,सभ्यता और शालीनता से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कई महिलाओं ने मंत्री,सांसद और विधायक बनकर ऐसा काम किया है या कर रही हैं जिससे योगी सरकार का मान बढ़ा। इन्हीं में एक हैं, मलिहाबाद की विधायक जय देवी,जो सादगी की मूरत हैं और उनके भाव में कहीं से भी सत्ता का दंभ नहीं दिखता। वे पूरी सादगी के साथ अपने घर का चूल्हा-चौका का काम निपटाने के बाद सुबह घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठ जाती हैं और फिर शुरु होती है विधायक जय देवी की अदालत...। गांव,गली और क्षेत्र से पीड़ित महिलायें,पुरुष,सभी फरियादी अपनी समस्याओं के अंबार लगा देते हैं लेकिन क्या मजाल विधायक जय देवी परेशान हों...। गांव वालों के साथ गंवई भाषा में आत्मीयता का बोध देते हुये समस्याओं को सुनती हैं। पुलिस-प्रशासन या गांव में जमीनों का विवाद हो,तुरंत दो मीनट में फैसला सुनाती हैं। जब उनके दरवाजे पर पीड़ित आते हैं तो चेहरों पर तनाव होता है लेकिन जाते समय सभी चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटते हैं, क्योंकि वे अपने विधायक नहीं बल्कि अपने दीदी अऊर बहनी के पास आकर फरियाद करते हैं। सबसे अच्छी बात जय देवी में ये दिखी कि वे भीड़ में बैठी होती हैं तो अनजान व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि उनके सामने मलिहाबाद की विधायक जय देवी बैठी हैं। बिल्कुल सादगी से भरपूर सलवार-सूट में फरियादियों को अपने अगल-बगल बिठाकर उनकी समस्याओं को सुनती है। जहां तक अंदाज की बात है तो जय देवी गांव वालों के साथ ठेठ गंवई अंदाज में बात करती हैं, तभी तो वे पीड़ितों के दिलों में घर कर जाती हैं। जय देवी तो विधायक हैं ही इनके पति हैं केन्द्रीय राज्य मंत्री व सांसद कौशल किशोर। कौशल किशोर भी अपनी जीवटता और जनमानस के बीच के नेता के रुप में विख्यात हैं। सीधी बात करें तो कौशल किशोर और जय देवी दोनों ही अवाम की सेवा के लिये ही बने हैं। मलिहाबाद की विधायक जयदेवी से खास बातचीत में द संडे व्यूज़ ने हर उन पहलुओं पर बात की जिसे सूबे की जनता जानना और सुनना चाहती है। उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ अपने और अपने पति के गर्दिश के दिनों से लेकर कैसे उनकी शादी हुयी,बच्चों ने कितनी गरीबी देखी...पर खुलकर बातचीत की। दोनों पति-पत्नी यानि केन्द्रीय राज्य मंत्री,सांसद कौशल किशोर और मलिहाबाद की विधायक जयदेवी ने गर्दीश के दिनों में भी लोगों को न्याय दिलाने के लिये ईमानदारी से खूब लड़ाई लड़ी और आज उस मुकाम पर हैं जहां आने के लिये दुनिया तरसती है। पेश है जय देवी से खास बातचीत के अंश...।

सवालः सुबह से ही आपके घर पर फरियादियों की भीड़ लग जाती है। आप कैसे मैनेज करती हैं?

शेष भाग पेज 6 पर

होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति अब अधिकारियों को देंगे नया टास्क...

बेहतर काम करने वाले अधिकारियों का बढ़ेगा मान, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई

अक्षत श्री.

लखनऊ। होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि मैंने सूबे के समस्त मंडलीय कमांडेंट की जिम्मेदारी तय कर दी थी कि वे कमांडेंट की कार्यशैली पर नजर रखें और उनसे बेहतर काम लें। मैंने युवा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे शानदार काम करें जिससे विभाग ऊंचाईयों की तरफ बढ़े लेकिन मेरी सोच के मुताबिक काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। 30 जून को तबादला नीति खत्म होने के बाद मैं बैठक करुंगा और साफ शब्दों में अधिकारियों से कहूंगा कि जिम्मेदारियों को निभाओ और विभाग को आगे ले जाने का काम करो। इसमें लापरवाही बरतने वालों को किसी सूरत में नहीं बख्शूंगा।

द संडे व्यूज़ से खास बातचीत के दौरान **मंत्री धर्मवीर प्रजापति** ने बताया कि फिलवक्त ट्रांसफर चल रहा है। मेरी कोशिश है कि लखनऊ सहित अन्य जनपदों में नीति के तहत ही सभी वर्ग का तबादला बिना भेद-भाव बरते हो। एक-एक नाम पर डीजी नजर रखकर काम कर रहे हैं।

मैंने स्पष्ट कर दिया है कि तबादला में बिना दबाव काम करें ताकि बेहतर अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिले और वे अपने काम के दम पर सरकार की छवि में चार चांद लगाने का काम करें। उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उस दौरान अधिकारियों को नया टास्क देंगे और उसे सभी को करना होगा ,क्योंकि काम के दम पर ही इस विभाग की पहचान बनी है। मेरी कोशिश रहेगी कि जनता के बीच होमगार्ड विभाग की पहचान सकारात्मक बने और अधिकारी पूरे मनोयोग से काम करें। मंत्री ने कहा कि मेरी कोशिश है कि अधिकारियों को काम करने का बेहतर माहौल दिया जाये, जिसमें डीजी बी.के. मौर्या के स्तर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है लेकिन कुछ अधिकारी उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि जो काम करेगा उसका मान बढ़ाया जायेगा और जो लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

संपादकीय

द संडे व्यूज़ 2

लखनऊ, रविवार, 25 जून 2023

विचार आपके, रखेंगे दमदार तरीके से

यदि आप समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो दफ्तरों में आपका शोषण होता है, स्कूलों में हो रही मनमानी से आहत हैं, तो अपने विचार को मुझसे साझा करें। नाम, पता गोपनीय रखा जायेगा। कृप्या इस मेल पर अपनी बात रखें e-mail:sanjaysrivastava.ss26.gmail.com Mob.: 9451949932

तीखी बात

जानलेवा गर्मी : तल्ख मौसम के मुकाबले हो योजनाबद्ध पहल

लखनऊ। देश में गर्मी की लहरें घातक दर से बढ़ रही हैं। भीषण गर्मी सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ जीवन और आजीविका के लिये गंभीर खतरा पैदा कर रही है। इससे श्रमिकों की उत्पादकता प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सप्ताह के अंत तक प्रचंड गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। झांसी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज व कानपुर में 45.1,आगरा व बांदा में 43. 8 हमीरपुर में 43.2, फतेहपुर में 43.6 और लखनऊ में 41 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 26 जून तक बढ़ा दी हैं। आईएमडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा और अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में हल्की बूंदा बांदी के आसार हैं। हालांकि इससे तापमान में कोई खास बदलाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि तापमान इतना क्यों बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम के चक्र में बदलाव और बढ़ते तापमान की सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। यानि जलवायु परिवर्तन ने बढ़ते तापमान को रोकना लगभग असंभव बना दिया है। शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, हरियाली कम हो रही है, इमारतों की तादाद बढ़ रही है और पेड़ कट रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है। अगर हमने बदलते मौसम के साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो स्थिति बिगड़ सकती है।

मौसम के बदलने के हिसाब से हमें अपने भोजन और रहने के तरीकों को भी सुधारना होगा। इस बीच भीषण गर्मी के मद्देनजर चिकित्सकों ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से शाम चार बजे के बीच जरूरी काम से ही घर अथवा दफ्तर से बाहर निकलें। पेट को पानी से भरा रखें। बासी और तला भुना खाने से परहेज रखें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें। बिगड़ते मौसम की चंचलता प्रभावी हस्तक्षेप से बच सकती है। इसलिये सबसे अच्छी उम्मीद शमन रणनीति में निहित है। शहरी बुनियादी ढांचे को कांच और कंक्रीट से दूर रखना चाहिये और पारंपरिक शीतलन प्रणाली को फिर से अपनाना चाहिये, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात गंभीर हो सकते हैं। हाल के दिनों में यूपी-बिहार समेत देश के कई राज्यों में गर्मी व लू से होने वाली मौतें हमारी गंभीर चिंता का विषय होनी चाहिये। विडंबना यह है कि लगातार बढ़ते तापमान के चलते जहां असहनीय गर्मी से मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है वहीं हमारी चिकित्सा सेवाएं उपचार के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसे सीधे तौर पर धरती के लगातार बढ़ते तापमान की परिणति के रूप में देखा जाना चाहिये। मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में ग्लोबल वार्मिंग का घातक प्रभाव नजर आने लगा है। यह रहस्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में चालीस डिग्री से अधिक तापमान के बीच बलिया जनपद में ही सौ से अधिक मौतें हुयी हैं। पूरे राज्य व बिहार के आंकड़ों को मिला दें तो चिंताजनक स्थिति सामने आती है।

बकौल सरकारी चिकित्सा अधिकारी, मरने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो उम्रदराज थे और कई अन्य रोगों से ग्रसित भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मौत का आंकड़ा एक खतरनाक संकेत है क्योंकि गर्मी इन मौतों का बड़ा कारण रही है। इसी तरह का संकट बिहार के कई जनपदों में देखने को मिला है। चिंता की बात यह भी है कि अभी मानसून आने में विलंब है और इन इलाकों में जल्दी आसमान से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते। निः संदेह, मौसम की तल्खी से होने वाली मौतों को कम करने के लिये देश में हीट एक्शन प्लान को सुनियोजित ढंग से लागू करने की सख्त जरूरत है। विडंबना यह है कि मौसम की तल्खी का मुख्य शिकार देश का गरीब तबका ही होता है जो शीतलहर, लू व बाढ़ की चपेट में आता है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक वर्ग। बहरहाल, प्रचंड गर्मी से उपजी हीट वेव से बचने के लिये उत्तर प्रदेश व बिहार आदि राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि जल्द बारिश के आसार नहीं हैं।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल स्थित बलिया में हुई अप्रत्याशित मौतों को लेकर अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं। विशेषज्ञों की टीमें वास्तविक कारण जानने के प्रयास कर रही हैं। वहीं गर्मी बढ़ने के बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। चिकित्सा अधिकारियों की दलील है कि मरने वाले लोग पहले अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। लेकिन सवाल चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी उठाये जा रहे हैं। मरीजों को पर्याप्त संख्या में बेड व समय पर उपचार न मिलने की बातें भी कही जा रही हैं। इसके विपरीत सरकारी अधिकारी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं होने की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि उम्रदराज मरीजों में बीमारियां तेज गर्मी के चलते गंभीर हो जाती हैं क्योंकि रोगों का संक्रमण बढ़ जाता है। हालांकि, रोज जीवनयापन के लिये गर्मी में निकलते समय लोग उन सामान्य बातों का ध्यान नहीं रखते जो बाद में लू लगने का कारण बनती हैं। जिसके चलते उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा हो जाती है। जो लू की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कर देती है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन सरकारी अधिकारी आग लगने पर कुआं खोदने की प्रवृत्ति से ग्रसित रहते हैं। निः संदेह, जनसंख्या दबाव के चलते सरकारी अस्पताल मरीजों के बोझ से चरमरा रहे हैं लेकिन समय रहते बचाव व उपचार की तैयारी जरूरी होती है। यह जानते हुये भी कि देश में गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या में साल दर साल इजाफा होता जा रहा है। वास्तव में देश में मौसम की तल्खी से मरने वाले मरीजों की व्यापक जांच होनी चाहिये और अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक बचाव व राहत के कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिये। सरकारी तंत्र को मौत के आंकड़ों में कमी दर्शाने व गर्मी के बजाय मौत के अन्य कारण बताने की प्रवृत्ति से बचना चाहिये। मौतों का अध्ययन यदि वैज्ञानिक तरीके से पारदर्शिता के साथ किया जायेगा तो इनके कारणों के निष्कर्ष तमाम लोगों का जीवन बचाने में सहायक हो सकते हैं।

साइबर सुरक्षा के लिये

साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से निकटता से जुड़ा मुद्दा है। ऑनलाइन सिस्टम से जितनी सुविधा हुयी व समय की बचत हुयी, उसकी सुरक्षा के लिये खतरा उतना ही ज्यादा बड़ा हो गया। अक्सर खबरें आती रहती हैं कि साइबर अपराधियों ने लोगों का निजी डाटा चुरा लिया है। गौरतलब है कि दुनिया में कई सरकारों के संरक्षण में हैकिंग का काम किया जा रहा है। जिस तेजी से टेक्नालाजी बदल रही है सुरक्षा उपायों में उसी तेजी से बदलाव करके चौकस व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। पिछले दिनों कोविड टीकाकरण के लिए बनाए गए सिस्टम कोविन के डाटा में सेंधमारी की चर्चा ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। क्योंकि आए दिन लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आते रहते हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया कि कोविन का कोई डाटा चोरी नहीं हुआ। सरकार के दावे को सही मान भी लिया जाये कि डाटा चोरी नहीं हुआ है तब भी जरूरी है कि सारे मामले की गंभीरता से जांच की जाए। दुनिया जानती है कि भारत एक बड़ा उभरता उपभोक्ता बाजार है और विश्व की तमाम कंपनियां अपने कारोबार को भारत में फैलाना चाहती हैं। यदि कोई डाटा चोरी होता है तो ये कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाने के लिये चोरी का डाटा खरीद सकती हैं। याद रहे भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए भी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। सरकार डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। इसलिये देश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है। डाटा चोरी के नियमन के लिये देश में पर्याप्त कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। कोशिश हो कि हैकरों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बनाये जायें। साइबर सुरक्षा के लिये भारत की राष्ट्रीय एजेंसी, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने देश की साइबर सुरक्षा से निपटने में प्रगति के साथ सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमलों में कमी की है। साइबर-सुरक्षित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, भारत को एक मजबूत साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता होगी, जो सरकारी प्रणालियों, नागरिकों और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करे। यह न केवल नागरिकों को साइबर खतरों से बचाने में मदद करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास भी बढ़ायेगा।

अशांत मणिपुर

मणिपुर में एक माह से अधिक समय से अशांति और हिंसक तनाव का माहौल बना हुआ है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद 50 हजार से अधिक लोग वर्तमान में राज्य भर के 349 राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य का मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है। अब कुकी समुदाय ने दावा किया है कि मणिपुर में वर्तमान स्थिति केवल इसलिये पैदा की गयी जिससे कुकी पहाड़ी हिस्सों से हट जायें। कुकी समुदाय की मांग है कि अब उन्हें मैतेई समुदाय से अलग रहने दिया जायेगा, राज्य में मैतेई बहुमत में हैं। राज्य पुलिस के सहयोग से सेना और अर्धसैनिक बल राज्य में शांति बहाल करने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं और केंद्र सरकार भी हालात पर नजर रख रही है। लेकिन हिंसा की घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा सका है। ताजा मामला खोखेन गांव का है जहां शुक्रवार को जवानों की वर्दी में आये मैतेई समुदाय के उग्रवादियों ने पहले कॉबिंग के बहाने ग्रामीणों को घरों के बाहर बुलाया और फिर उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गयी। कुछ दिनों पहले असम राइफल्स के शिविर पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया और वहां घायल एक बच्चे को जब उसकी मां के साथ एंबुलेंस में ले जाया जा रहा था, तो उग्र भीड़ने एंबुलेंस को घेर कर उसमें आग लगा दी। उधर सरकार ने राज्य में इंटरनेट पर बैन 15 जून तक के लिये बढ़ा दिया है। राज्य में इंटरनेट बैन करने का फैसला पहली बार मई के पहले हफ्ते में लिया गया था।

गौरतलब है कि इंटरनेट बंद होने से रोजमर्रा के कामकाज और कारोबार में अड़चनें आ रही हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान के दौरान लोगों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किये जा रहे हैं। जाहिर है हिंसा को जारी रखने के लिये कहीं न कहीं से हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। हालात बता रहे हैं कि इस तरह की हिंसा को भड़काने की तैयारी काफी पहले से की जा रही होगी। सीबीआई इस बात का पता लगायेगी कि कुकी और मैतई समुदाय के बीच हिंसा किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। सवाल ये है कि सरकार मणिपुर में स्थिति की गंभीरता का आकलन पहले क्यों नहीं कर पायी। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर में उग्रवाद की समस्या पहले से है, फिर क्यों खुफिया एजेंसियों ने इस बात की सतर्कता नहीं बरती कि स्थानीय लोगों तक हथियार न पहुंचें। इस समय मणिपुर में शांति बहाल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथिकता होनी चाहिये।

मणिपुर में एक माह पहले दो समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा की घटनाओं का पटाक्षेप न हो पाना बताता है कि राज्य में विवाद व अविश्वास की जड़ें गहरी हैं। वहीं अलग-अलग नस्ली समूहों के बीच शांति स्थापना के मकसद से बनायी गई शांति समिति की गठन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल समस्या की जटिलता की ओर इशारा कर रहे हैं। जाहिर है कि कूकी समुदाय के लोगों का भरोसा जीते बिना शांति के प्रयास सिरे चढ़ाने मुश्किल ही होंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि

इस गैर जरूरी विवाद में अब तक सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 50 हजार के करीब लोग बेघर हो गये हैं। नीति-नियंताओं को ध्यान रखना चाहिये कि यह सीमावर्ती राज्य कई दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहां के टकराव की तपिश निकटवर्ती राज्यों में भी फैल सकती है। चिंता की बात यह है कि ककी समुदाय के लोग शांति समिति के पैनल में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह व उनके समर्थकों की उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि कूकी समुदाय के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठन के लोग भी शांति समिति में शामिल किये गये हैं। वहीं कूकी समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना उन्हें शांति समिति में शामिल किया गया है। बहरहाल, कुल मिलाकर मणिपुर का यह संघर्ष राष्ट्र के संघीय ढांचे की भावना के विपरीत दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा। केंद्र सरकार की भी कोशिश होनी चाहिये कि राज्यपाल के नेतृत्व वाली समिति के 51 सदस्यों को लेकर सभी पक्षों की सहमति बने। वहीं कूकी समुदाय के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके वार्ता के लिये अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करे। कूकी समुदाय के विरोध के मूल में एक आरोप यह भी है कि उनके खिलाफ अभियान चलाने वाले एक नागरिक समूह के सदस्यों को शांति समिति में शामिल किया गया है। दरअसल, मणिपुर में हुये हालिया संघर्ष के मूल में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाना बताया जाता है। इस निर्णय के विरोध स्वरूप उपजे विवाद के चलते ही राज्य हिंसा की चपेट में आ गया। दरअसल, करीब 53 फीसदी आबादी वाले मैतेई समुदाय के पास राज्य में महज 10 फीसदी जमीन है जबकि 40 फीसदी आबादी वाले कूकी समुदाय के पास 90 फीसदी जमीन है।

यह असंतुलन अकसर दोनों समुदायों में टकराव का कारण बनता रहा है। यह पहले से ही कयास लगाये जा रहे थे कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिये जाने के बाद राज्य में अशांति का माहौल बन सकता है। कालांतर ऐसा हुआ भी। सतही तौर पर राज्य में हिंसक वारदातें थमी नजर आती हैं लेकिन इस विवाद का पटाक्षेप जल्दी हो पायेगा, ऐसे आसार नजर नहीं आते। आबादी और जमीन के असंतुलन का विवाद तुरत-फुरत थमता नजर नहीं आता है क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में इस अनुपात में बड़ा परिवर्तन संभव भी नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री के हस्तक्षेप व सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के बावजूद सतही शांति तो नजर आती है। सवाल है कि यह स्थिति कब तक कायम रह सकती है। वह भी तब जब मैतेई समुदाय आरक्षण को अपने जीवन के लिये जरूरी बता रहा है तो आदिवासी समुदाय इसे क्षेत्र में असंतुलन पैदा करने वाला बता रहा है। कूकी समुदाय इसे अपने अस्तित्व के लिये खतरा बताता है। जाहिर है इस जटिल समस्या का समाधान दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़ाकर ही किया जा सकता है। यह विश्वास दोनों पक्षों के बीच बातचीत बनाये रखने से ही बढ़ेगा। यह कार्य सुरक्षा बलों की तैनाती से भी संभव नहीं होगा क्योंकि क्षेत्र में चरमपंथियों की सक्रियता का इतिहास भी रहा है। ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि पुलिस-प्रशासन बिना किसी पक्षपात के कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। वहीं कूकी समुदाय की उस बात पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिये जिसमें शांति समिति में केंद्र के अधिकारियों की बड़ी भूमिका रखने की मांग की जा रही है।

all pages:20 JAN Page 1.qxd 6/30/2023 2:46 AM Page 3

ज्योति मौर्या की 6 साल की नौकरी, खड़ी कर ली 5 करोड़ की कोठी...

पीसीएस ज्योति मौर्या की अनसुनी कहानी : फर्जी मार्कशीट लगाकर पाई नौकरी और पांच वर्ष में बन बैठी करोड़पति

शेखर यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी को मजाक बनाने वाले पीसीएस ज्योति मौर्या अब शासन से लेकर अवाम के लिये पहेली बन चुकी हैं। सुर्खियों में आने की कई वजह है। पीसीएस बनने से पहले बीएड की फर्जी मार्कशीट लगाकर टीचर बनी, कमांडेंट मनीष दूबे से अवैध संबंध और काली कमाई वाली डॉयरी का खुलना...। सीधी बात करें तो ज्योति मौर्या ईमानदार नहीं भ्रष्ट महिला अधिकारी हैं। वर्ष 2011 में 72000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गयी थी जिसमें बी.एड. मांगा गया था। ज्योति मौर्या का उस वक्त बी.एड. पूरा नहीं हुआ था। अंतिम तिथि वर्ष 2011 ही था लेकिन वे मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने 2011 का फर्जी मार्कशीट बनाकर आवेदन कर दिया। जिस दिन काउंसलिंग हो रही थी न्यायालय ने शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी। तीन वर्ष बाद न्यायालय के फैसले के बाद फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया। ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया था कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2011 में आवेदन किया था,वही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बस इसी का फायदा उठाते हुये ज्योति मौर्या ने ऑनलाइन आवेदन में बी.एड. का प्राप्तांक भी डाल दिया और बी.एड. 2011 का फर्जी प्राप्तांक बनाकर संलग्न करा दिया जबकि हकीकत में ज्योति मौर्या ने वर्ष 2012 में बी.एड. पासिंग आउट किया है। इनका चयन प्राथमिक विद्यालय अजनौरा,जसवंतनगर,इटावा में किया गया। यानि,धोखेबाजी की नींव ज्योति मौर्या ने पहली नौकरी पाने के समय ही रख दी थी और उस राह में ये इतनी आगे निकल गयी कि अवैध कमाई ने इन्हें इस कदर अंधा कर दिया कि अपने परिवार की खुशियों को भी ताख पर रखी दीं। चौंकाने वाली बात यह है कि योगीराज में इस तरह की भ्रष्ट महिला अधिकारी को शासन में बैठे अफसरान बचाने में लगे हैं। क्यों?

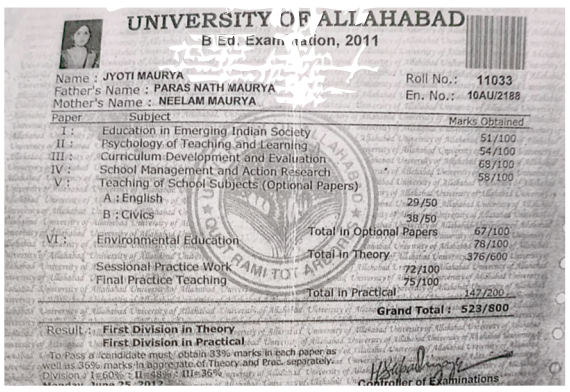

UNIVERSITY OF ALLAHABAD
B.Ed. Examination, 2011

Name : JYOTI MAURYA
Father's Name : PARAS NATH MAURYA
Mother's Name : NEELAM MAURYA
Roll No.: 11033
En. No.: 10AU/2188

Paper	Subject	Marks Obtained
I :	Education in Emerging Indian Society	51/100
II :	Psychology of Teaching and Learning	54/100
III :	Curriculum Development and Evaluation	69/100
IV :	School Management and Action Research	58/100
V :	Teaching of School Subjects (Optional Papers)	
	A : English	29/50
	B : Civics	38/50
	Total in Optional Papers	67/100
VI :	Environmental Education	78/100
	Total in Theory	376/600
	Sessional Practice Work	72/100
	Final Practice Teaching	75/100
	Total in Practical	147/200
	Grand Total :	523/800

Result : First Division in Theory
First Division in Practical
To Pass a candidate must obtain 33% marks in each paper as well as 36% marks in aggregate of Theory and Prac. separately.
Division : I=60% : II=48% : III=36%

Controller of Examinations

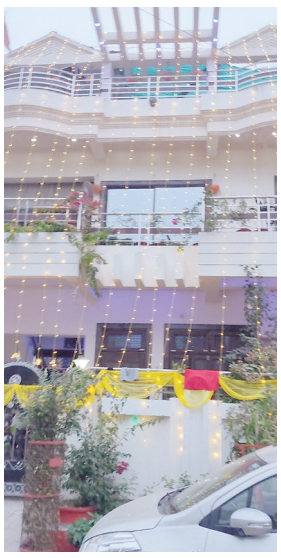

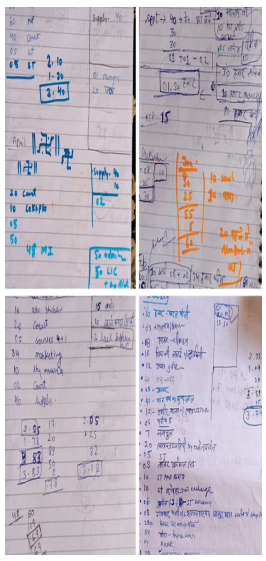

द संडे व्यूज़ ने सबसे पहले पीसीएस ज्योति मौर्या और कमांडेंट मनीष दूबे द्वारा मिलकर व्हाटसअप पर अपने पति आलोक मौर्या की हत्या कराने की प्लानिंग का खुलासा किया। उसके बाद तो मीडिया में दोनों की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी लेकिन अब हम सिर्फ ज्योति मौर्या की करोड़ों की संपत्ति से लेकर कूटरचित दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने का खुलासा करेंगे। ये द संडे व्यूत नहीं बल्कि ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या बता रहे हैं। शिक्षक बनने में फर्जी मार्कशीट लगाने के प्रकरण पर उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिखकर हंगामा मचा दिया है।

इटावा के जसवंतनगर में शिक्षक बनने के बाद वेतन लेकर ज्योतिम मौर्या ने साबित कर दिया कि वे सरकारी खजाने में सेंध लगाने का भी दम रखती हैं। पहली ही नौकरी कूटरचित एवं फर्जी मार्कशीट से शिक्षक फिर समीक्षा अधिकारी बनने के सफर तक ज्योति मौर्या को भ्रष्टाचार की रोटी खाने में मजा आने लगा। इसी दौरान इन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी और उसमें इनका चयन हो गया। पीसीएस में तो इन्होंने ओरिजनल मार्क शीट लगाया है लेकिन इन्हें ये समझ में आ गया कि सरकार ने उन्हें एसडीएम की कुर्सी पर बिठा दिया है तो अब डंके की चोट पर लूट लो...किसी की जुर्रत नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके...। ये जिस जनपद में रहीं पैसा लेकर स्टे देना,मार्केटिंग इंस्पेक्टर,सप्लाई इंस्पेक्टर,लेखपाल से लेकर खनन माफियाओं से प्रति माह चार से पांच लाख रुपये की काली कमाई करने लगीं। ज्योति मौर्या ने ऑडियो में कुबूला है कि इलाहाबाद में उनकी 5 करोड़ की कोठी भी है। हिम्मत की दाद तो देनी ही चाहिये कि बेगुनाहों को फंसाने और खनन माफियाओं से वसूली की कहानी लिखने वाली मैडम बेखौफ होकर अवैध रकम की स्क्रीप्ट पर्सनल डायरी में लिखती थी। ये साबित करता है कि सरकार या शासन का किसी तरह तरह का डर उनके मन में नहीं था। ज्योति मौर्या के बीएड के अंकपत्र की जांच होनी चाहिये। डॉयरी में लिखी गयी काली कमाई की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिये ताकि इस बात का खुलासा हो कि आखिर इन्होंने कितने करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है? इस समय ज्योति मौर्या चीनी मिल,बरेली में महाप्रबंधक पद पर तैनात हैं,वहां भी जांच करायी जाये तो इनके स्तर से बड़े फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। बात जो भी हो,अब सरकार को तय करना है कि भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखने वाली पीसीएस ज्योति मौर्या के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि हराम की रोटी खाने वाले अधिकारियों के पसीने छूट जाये।

पीसीएस ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने अपने बयानों से मीडिया में सनसनी मचा दी है। अपनी पत्नी ज्योति मौर्या पर अवैध संबंध से लेकर भ्रष्टाचार का रिकार्ड तोड़ने वाली ज्योति मौर्या का असली चेहरा जनता को दिखा दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने खुलासा किया है कि ज्योति मौर्या सरकारी नौकरी पाने के लिये पहली सीढ़ी गलत तरीके से चढ़ी। वर्ष 2011 की विशिष्ट बी.टी.सी. शिक्षक भर्ती में ज्योति मौर्या ने फर्जी तरीके से कूटरचित अंक पत्र तैयार कर आवेदन पत्र में गतल सूचना भरकर इटावा जनपद में शिक्षक के रुप में प्रशिक्षण के लिये प्राथमिक विद्यालय अजनौरा, जसवंतनगर में नियुक्ति पायी। जसवंतनगर में ग्रामीण बैंक में ज्योति मौर्या के नाम से एकाउंट नंबर 00051100210 2538, आईएफएससी कोड यूपीसीबी00 इटावा, पेनकार्ड बीक्यूएमपी..... बी, मोबाइल नंबर 9453423719 दर्ज है। जब आवेदन हो रहा था उस समय ज्योति मौर्या का बी.एड.चल रहा था और इसकी अंतिम तिथि वर्ष 2011 ही था। अब नौकरी पाने की जल्दबाजी में आवेदन पत्र में प्राप्तांक की जगह को उन्होंने खाली रखा। पूर्णांक निश्चित होता है इसलिये उसे भरकर आवेदन कर दिया। एक वर्ष बाद काउंसलिंग शुरु हुयी। काउंसलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों के हाथों में आवेदन पत्र दिया जाता है,उसी का फायदा उठाते हुये ज्योति मौर्या ने तुरंत खाली जगह पर अपना पूर्णांक भरकर काउंसलिंग कराया। उसी दिन न्यायालय ने पूरे भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी मामला तीन वर्ष तक न्यायालय में चलता रहा। न्यायालय का निर्णय आने के बाद पुनः ऑनलाइन आवेदन मांगा गया परन्तु उसमें यह उल्लेख किया गया कि जिन लोगों ने वर्ष 2011 में आवेदन किया था,वही लोग आवेदन करेंगे। इसका फायदा उठाते हुये ज्योति मौर्या ने इस बार ऑन लाइन आवेदन में बी.एड. का प्राप्तांक भी डाल दिया तथा बी.एड. 2011 का अंकपत्र फर्जी तरीके से बनवाकर संलग्न कर दिया जबकि ओरिजनल अंक पत्र में बी.एड. 2012 पासिंग आउट किया

है। सचिव को लिखे गये पत्र में यह भी लिखा है कि ज्योति मौर्या ने पहली ही नौकरी कूटरचित एवं फर्जी तरीके से हासिल की और उसी के आधार पर समीक्षा अधिकारी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका चयन हुआ था।वे पीसीएस बन गयीं,फिर क्या था। जो उन्हें रिश्वत देता,वे उसी के हक में फैसला सुनाने लगीं,उन्हें सिर्फ नोटों की गड्डी रास आने लगी और वे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबती चली गयीं। ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने बताया कि जब उनका ट्रांसफर होता तो अधिकारियों से कहती कि मेरे पति प्रतापगढ़ में अधिकारी हैं,इसलिये मेरा तबादला आसपास ही किया जाये ताकि परिवार के साथ रह सकूं। वे ट्रांसफर रुकवाने में भी मेरे नाम का दुरुपयोग करती रहीं और आज जब पूरे देश में बदनामी हो रही है तो मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न और लाखों रुपये मांगने का फर्जी आरोप लगा रही हैं। सीबीआई या विजीलेंस से जांच करा ली जाये कि इलाहाबाद में उनकी कोठी की कीमत क्या है? आखिर ज्योति मौर्या ने छह साल की नौकरी में कितना सैलरी ले ली की पांच करोड़ की कोठी खड़ा कर ली? शासन को जांच करनी चाहिये कि फर्जी मार्क शीट उन्होंने कहां से बनवाया,इससे फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का खुलासा होगा। जब सरकार फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वालों को जेल भेज रही है तो ज्योति मौर्या पर मेहरबानी क्यों? इन्हें भी जेल की सलाखों में भेजा जाये। इस बारे में ज्योति मौर्या के नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गयी लेकिन मोबाइल स्वीच ऑफ था।

गरीब नवाज...

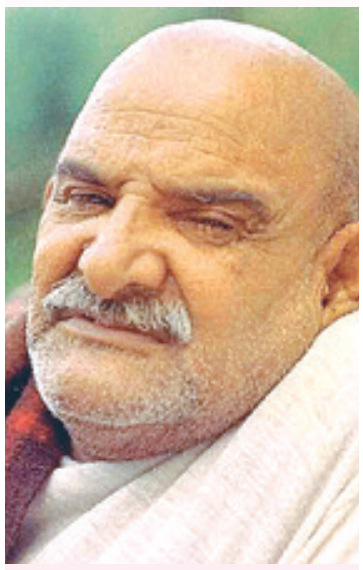

महाराज जी जब भी कानपुर जाते थे,वहां कुछ दिन ठहरते थे। वहां एक अमीर परिवार महाराज जी का भक्त था। एक बार काफी आग्रह पर महाराज जी उसके घर गये। वे अपने कई भक्तों के साथ थे। परिवार वालों ने पूजा की फिर कई तरह के व्यंजन तैयार कर महाराज जी की सेवा में अर्पित किया। वे महाराज जी को बताने की कोशिश करने लगे कि तमाम व्यंजनों में से पहले क्या खाये,उसके बाद क्या खाये और फिर उसके बाद...। महाराज जी ने मिठाई,कढ़ी,फल,सब्जी... सबको एक साथ कटोरे में रखा और एक साथ मिलाकर खा गये। खाने के बाद उन्होंने सेठ के ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी में बैठकर चले गये। यही ड्राइवर उन्हें अमरकंटक तक ले गया था। महाराज जी ने ड्राइवर से कहा अब हम तेरे घर चलेंगे। वह ड्राइवर एक मलिन बस्ती की झोपड़ी में रहता था। उसे सहसा महाराज जी पर विश्वास नहीं हो रहा था, परन्तु वे हठ कर रहे थे। उसके घर पहुंचकर महाराज जी ने कहा हमें भूख लगी है,हमारे लिये खाना ला...। गरीबी के कारण उसके घर में कुछ भी नहीं था। परिवार के लोग खाना खा चुके थे। फिर से रोटी बनाने में समय लगता। महाराज जी बोले, वहां पर डिब्बे में गुड रखा है,वही ला। ड्राइवर उसी जगह पर गया उसे गुड का डिब्बा मिल गया। महाराज जी ने उसे बड़े स्वाद से खाया। एक बार एक भक्त ने कहा कि महाराज जी आपतो सिर्फ धनी व्यक्तियों के यहां ही जाते हैं। उसके बाद उसे वे एक मोची के पास ले गये,जहां छोटे और सीलन भरे कमरे में कई दिनों तक रहे। हालांकि साथ के भक्तों ने काफी परेशानी महसूस की परन्तु महाराज जी प्रसन्न थे। जब वे गरीब लोगों के बीच होते हैं तो खूब प्रसन्न दिखायी देते। उस समय उनके चेहरे पर दयाभाव और प्रफुल्लता अधिक दिखायी देती है। बाबा हनुमान जी के दूसरे रूप में जाने जाते हैं इसलिये वे अपने भक्तों से कहते हैं कि राम के नाम का जाप करो...। राम, राम...

all pages:20 JAN Page 1.qxd 6/30/2023 2:46 AM Page 4

लोकसभा चुनाव 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा

डॉ.अजय कुमार मिश्रा

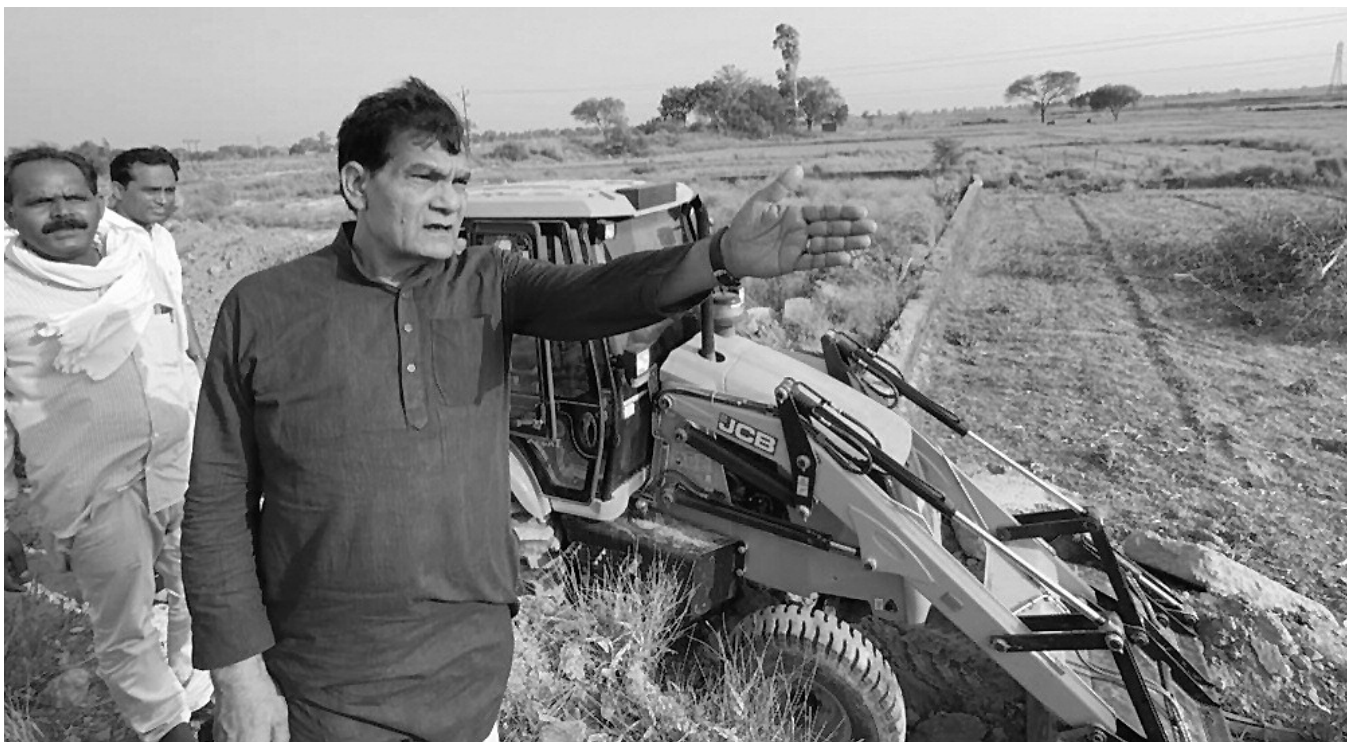

लखनऊ। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2024 में महज सात महीने की अवधि अब शेष है। हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम ने केंद्र सरकार को पुनः उत्तर प्रदेश पर गहराई से फोकस करने हेतु सजग किया है, क्योंकि देश की सत्ता की चाभी उत्तर प्रदेश की सहमति के बिना संभव नहीं है। सर्वाधिक लोकसभा सीट 80 उत्तर प्रदेश में ही है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदेश में लागू करने में उत्तर प्रदेश सरकार अव्वल भी रहा है, पर यदि यहां की आम जनता की आवश्यकताओं को मूल्यांकित कर प्राथमिक आवश्यकताओं का चुनाव करना हो तो बिजली की आपूर्ति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। रोजगार, स्व-रोजगार सभी की धूरी बिजली पर निर्भर करती है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री की भूमिका अति महत्वपूर्ण रूप से निकलकर सामने आती है, जिन्होंने महज एक वर्ष के कार्यकाल में अपने निर्णय से यह सुनिश्चित कर दिया है की प्रत्येक आदमी तक न्यूनतम मूल्य पर बिजली पहुचाने के लिये वो न केवल प्रतिबद्ध हैं बल्कि लगातार बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं। इनकी प्रतिबद्धता को प्रमाणित सिर्फ एक तथ्य और आकड़ों से भी किया जा सकता है की यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव ऊर्जा के लिये आये हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में भारी वृद्धि की पूर्ति के लिये ऊर्जा मंत्री ने जिस संजीदगी से कार्य किया है वह वास्तव में सराहनीय है । सीमित अवधि में एक दो नहीं बल्कि अनेकों जन-उपयोगी निर्णय लेकर सभी के हितों की रक्षा कर रहे हैं। यह सर्वविदित है की बिजली की मांग और पूर्ति की समस्याएं उत्तर प्रदेश में दशकों से विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में रही है। पर ठोस रणनीति बनाकर ऊर्जा मंत्री के अब तक के किये गये काम यह सुनिश्चित कर रहें है की जनता उनसे जुड़ने लगी है और किये गये कार्यो से प्रभावी भी है। इसका सकरात्मक परिणाम हालिया नगर निकाय चुनाव में भी दिखा है और लोकसभा 2024 के चुनाव में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में सामने दिखेगा। खास कर किसानों के लिये किये गये काम न केवल उपयोगी है बल्कि चर्चा का विषय भी है। किये गये कार्यो में से महत्वपूर्ण पर चर्चा करना यहां जरुरी है। बिजली की आपूर्ति में व्यापक सुधार करते हुये यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 से 22 घंटे तथा जिला मुख्यालय को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो। 1,21,324 मजरों का विद्युतिकरण का काम पूरा किया गया है तथा 1 करोड़ 58 लाख घरों का विद्युत संयोजन किया गया है। 33-11 के.वी. के 749 नये विद्युत उपकेन्द्र की न केवल स्थापना की गयी है बल्कि 1503 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि भी की गयी है । 1931 गाँवों, मजरों, जिनकी आबादी 1000 से अधिक है में 26,805 कि.मी. ए.बी. केबल लगाये गये हैं । 8.60 लाख उपभोक्ताओं के यहां बिजली मीटर लगाये गये, जिनके यहां पहले बिजली मीटर नही थे, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 30,462 मेगावाट किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण के लिये रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलायी जा रही है। निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में वर्षो से लगा प्रतिबंध समाप्त कर के किसानों को बढ़ा लाभ दिया गया है इससे एक लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये निजी नलकूपों के बिजली बिलों में शत- प्रतिशत की छूट प्रदान करना एक बड़ा साहसिक कदम है। खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदलने की अनिवार्यता आम लोगों के हितों में है। 2,10,436 निजी नलकूपों का सयोजन किया गया है, किसानों के लिये अलग से 2390 ग्रामीण विद्युत फीडर बनाये गये है, निजी पूंजी निवेश से 2035 मेगावाट क्षमता की तथा रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट की 256 मेगावाट क्षमता की शौर्य परियोजनाओं की स्थापना की गयी है। इसी तरह, सार्वजनिक रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था हेतु 21,197 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रो की स्थापना की गयी है, कंप्रेस्ड बायों गैस प्लांट, बायो कोल, बायो डीजल, बायो एथेनाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सौभाग्य योजना चलाकर सोलर पॉवर पैक संयंत्रो की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। अभी तक 53,354 की स्थापना की जा चुकी है,नये बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिये झटपट पोर्टल के जरिये आवेदन प्राप्त कर त्वरित गति से कम से कम समय में नया कनेक्शन प्राप्त करना है। अल्पकालीन त्वरित निर्णय जिनके आधार पर कहा जा सकता है की ऊर्जा विभाग में न केवल व्यापक बदलाव के साथ बड़े परिवर्तन हुये हैं बल्कि परिणाम भी सामने आना शुरू हो गया है।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से नीति बनाकर वर्ष 2024- 25 तक वितरण हानियों को कम करना, लॉस रिडक्शन, हर घर स्मार्ट मीटर को पहुचाना एवं विद्युत् तंत्र को आधुनिकीकरण करना निर्धारित लक्ष्य है, जिन पर तेजी से काम हो रहा है। इन कार्यो के लिये कुल रुपया 54,300.29 करोड़ धनराशी की आवश्यकता है जिनमे से 35,384.09 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, शेष धनराशी की स्वीकृति किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। विद्युत विभाग में दिसम्बर 2022 तक कुल 96.77 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया है जबकिविद्युत समाधान सप्ताह में 1.46 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया है। सम्भव पोर्टल पर 1,04,510 शिकायतों का समाधान किया गया है । बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में व्यापक सुधार करते हुये उत्पादन को 30,462 मेगावाट तक पहुंचाया गया है तथा वृद्धि हेतु कई काम चल रहे हैं। सभी को 24-7 बिजली आपूर्ति के लिये प्रदेश में 13 तापीय परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है । 765, 400, 220, 132 के.वी.उपकेन्द्रों का निर्माण कई जिलों में कराया गया है जो वर्षो से अति आवश्यक थे। यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में सर्वाधिक प्रस्ताव रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कुल 385 एम.ओ.यू. के माध्यम से 6.33 लाख करोड़ का प्राप्त हुआ है। सौर्य ऊर्जा नीति 2022 में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु लक्ष्य बनाकर काम किया जा रहा है। इसी तरह, बायो ऊर्जा नीति 2022 के जरिये लक्ष्य निर्धारित करके काम किया जा रहा है साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की मोनिटरिंग और सफल संचालन के जरिये उद्देश्य प्राप्ति हेतु विभाग में अलग-अलग पदों पर कुल 892 लोगों की नियुक्ति की गयी है।

ऊर्जा मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली के लिये किये जा रहें कार्यो के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा की आम आदमी का जीवन न केवल बेहतर हो रहा है बल्कि दूरगामी रणनीति बनाना यह सुनिश्चित कर देगा की बिजली की समस्या जड़ से समाप्त हो जायेगी। जिसका सीधा श्रेय नेतृत्व करता ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा को जाता है। आम जनता के जीवन की महत्वपूर्ण धूरी बिजली है फिर चाहे घर हो या बाहर, रोजगार हो या स्व- रोजगार, शिक्षा और तकनीकी, सभी से जुड़े रहने में महत्वपूर्ण कड़ी बिजली है। इसकी पूर्ति होने पर जनता का लगाव सीधे सरकार से होता है और परिणाम चुनाव में सकारात्मक रूप में दिखते हैं। देश की केंद्र सरकार का सहयोग ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिये महत्वपूर्ण है। अभी तक किये गये प्रयासों से परिणाम सामने दिख रहा है और जनता का सहयोग भी सरकार के प्रति प्रदर्शित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मंत्रियों और विभागों द्वारा किये गये कार्यो के साथ-साथ ऊर्जा विभाग अपने महत्वपूर्ण भूमिका से अहम् रोल आगामी चुनाव में निभाने को तैयार है । अब जरुरत है तो बस अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हो कर लगातार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की।

दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात के बाद जयपुर में गहलोत से मिले वेणुगोपाल

दिल्ली। दिल्ली और जयपुर के बीच इन दिनों सियासी मुलाकातों का दौर तेज है। इसी बीच एक बार फिर दिल्ली और जयपुर से सियासी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की पहले दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात हुई तो वहीं अब वेणुगोपाल की जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है। हालांकि के.सी. वेणुगोपाल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव की बेटी के शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं लेकिन उन्होंने इस दौरान जयपुर के एक होटल में अशोक गहलोत से भी मुलाकात की।

के.सी. वेणुगोपाल की दिल्ली में गुरुवार को सचिन पायलट से भी लंबी मुलाकात हुई जिसमें सुलह के फार्मूले को लागू करने पर लंबी चर्चा हुई। इसके बाद जयपुर पहुंचे वेणुगोपाल ने जयपुर के एक निजी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। यह मुलाकात भी लगभग एक घंटे चली। जिसमें राजस्थान के चुनाव के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। दरअसल 29 मई को दिल्ली में राजस्थान के सुलह का फार्मूला तैयार किया गया, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाजुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वैणुगोपाल ने सियासी गुफ्तगू की। दिल्ली की प्रयोगशाला में तैयार सुलह के फार्मूले पर राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच चुनाव को लेकर रजामंदी कराई गई थी। जिसके बाद ऐलान किया था कि राजस्थान में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब एक बार फिर वेणुगोपल ने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच अफवाहों का बाजार गर्म था कि 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट नई पार्टी का एलान कर सकते हैं, लेकिन सारी चर्चाएं कोरी साबित हुई और पायलट ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में अब राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज है। ऐसे में आगामी दिनों में कई और सियासी मुलाकाते होने की चर्चाएं हैं।

राममंदिर के लिए विदेशी भक्त भी कर सकेंगे दान

लखनऊ। विदेश में रहने वाले रामभक्त भी अब जल्द ही राममंदिर निर्माण के लिये निधि समर्पण कर पायेंगे। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नवंबर तक विदेशी दान लेने में सक्षम हो जायेगा। ट्रस्ट की ओर से एफसीआरए में पंजीकरण का आवेदन पहले ही किया जा चुका है।

ट्रस्ट ने राममंदिर निर्माण के लिये वर्ष 2021 में निधि समर्पण अभियान चलाया था। पूरे देश में चले इस अभियान में मंदिर निर्माण के लिये रामभक्तों ने करीब 3500 करोड़ का दान किया था। उस समय विदेशी रामभक्त मंदिर निर्माण के लिये निधि समर्पण नहीं कर पाये थे, क्योंकि ट्रस्ट विदेशी दान लेने में सक्षम नहीं था। जब तक गृहमंत्रालय की ओर से ट्रस्ट का पंजीकरण एफसीआरए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत नहीं हो जाता, तब तक ट्रस्ट विदेशी श्रद्धालुओं से सहयोग राशि स्वीकार करने में असमर्थ है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि आये दिन विदेशी भक्तों का फोन निधि समर्पण करने की मंशा से आता है, लेकिन जब उन्हें मना किया जाता है तब वे निराश हो जाते हैं। बताया कि अब विदेशों में रहने वाले रामभक्तों को जल्द ही निधि समर्पण करने की सुविधा मिल सकेगी। ट्रस्ट ने एफसीआरए में पंजीकरण के लिये आवेदन कर दिया है, उम्मीद है कि नवंबर तक पंजीकरण हो जायेगा। पंजीकरण होते हुये भक्त राममंदिर के लिये अपना अंशदान दे सकेंगे। बताया कि इसके लिये नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा में खाता भी खोला जा चुका है। विदेशी दान इस खाते में स्वीकार किया जायेगा।

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिये हर माह करीब 1.5 करोड़ का दान आ रहा है। बताया कि गर्भगृह में रखे दानपात्र से हर माह औसतन 60 से 70 लाख का चढ़ावा प्राप्त हो रहा है। इसी तरह ट्रस्ट कार्यालय व दर्शनमार्ग पर बने काउंटर पर हर करीब डेढ़ से दो लाख की नकदी आ रही है। ऑनलाइन माध्यमों सहित चेक, आरटीजीएस के जरिये भी भक्त दिल खोलकर दान दे रहे हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में सोने-चांदी का दान भी भक्तों द्वारा किया जाता है।

यमुना के पानी से दूषित हो रहीं सब्जियां, संसद में मुद्दा उठाऊंगा :मनोज तिवारी

दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी के दूषित पानी को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आमतौर पर यमुना नदी के किनारों पर उसके पानी से ही खेती की जाती है। इस दूषित पानी की वजह से सब्जियां भी दूषित हुई हैं, जिन्हें नदी के किनारों पर उगाया जाता है। ये सब्जियां दिल्ली-एनसीआर के घरों में पहुंच रही हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वह यमुना के पीनी की वजह से दूषित हो रहीं सब्जियों के मुद्दों को लोकसभा में उठायेंगे।

मनोज तिवारी ने कहा कि न्यूज9 प्लस की टेस्ट रिपोर्ट हैरान करने वाली हैं। अब तक हम यही मानते थे कि सिर्फ यमुना का पानी दूषित हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि सब्जियां भी दूषित हो रही हैं। उनका कहना है कि यमुना के किनारे से इकट्ठा किये गये सैंपल्स लोगों के स्वास्थ्य के लिये जहरीले और हानिकारक हैं। ये निःसंदेह बहुत हैरान करने वाला है। बीजेपी सांसद आगे कहा कि इसीलिये मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ राजनीतिक तौर पर बात करने के बजाय हमें मिल- बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिये। ये मुद्दा सीधे तौर पर दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं समय-समय पर यह मुद्दा उठाता रहा हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली है, वह भी इससे प्रभावित हैं, क्योंकि यमुना वहां से भी बहती है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना साफ करने वाली बातों का जिक्र करते हुये मनोज तिवारी ने उन पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा है कि 2025 तक यमुना को साफ कर दिया जायेगा लेकिन यह पहली बार नहीं है कि दिल्ली सरकार ने इस तरह का वादा किया है। मुख्यमंत्री इससे पहले भी कई बार इसी तरह का ऐलान कर चुके हैं। 2013 में उन्होंने कहा था कि 2018 तक यमुना साफ हो जायेगी। फिर 2018 में कहा गया है कि ऐसा 2020 तक होगा और जब 2020 आया तो कहा गया कि 2025 में नदी साफ कर दी जायेगी। अब हम 2023 के बीच में हैं और कोई भी काम नहीं हुआ है, जबकि इस पर अब तक करीब 8000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।मनोज तिवारी ने कहा कि हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। मैं अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठायेंगे। हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं।

फरीदाबाद की बड़खल झील, 60 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण

हरियाणा भारत के प्राचीन और खूबसूरत राज्य में से एक है। कहीं पर ऐतिहासिक इमारतें तो कहीं पर खूबसूरत सरोवर, खूबसूरती हरियाणा के कोने-कोने में बसी है। इसी कड़ी में हम आपको फरीदाबाद की एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जो कभी एक वक्त पर पर्यटकों से गुलजार रहा करती थी पर बीतते वक्त के साथ झील का पानी कम होता गया और पर्यटक भी कम होते चले गए।

फरीदाबाद की बड़खल झील की हालात पहले ऐसे नहीं थी. देश के कोने-कोने से लोग यहां घूमने आते थे. यहां बोटिंग, घुड़सवारी और ऊंट की सवारी का लुत्फ लेते थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ इस खूबसूरती को मानों किसी की नजर लग गई हो और जैसे-जैसे झील का पानी कम होता गया, यहां आने वाले लोगों की संख्या भी कम होती गई. लोगों की चहल-पहल से हमेशा भरी रहने वाली ये जगह वक्त के साथ सुनसान होती चली गई।

झील को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखी है. फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत 60 करोड़ की लागत से बड़खल झील का दोबारा सौंदर्यीकरण किया जाएगा. स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की मानें तो इस साल के अंत तक बड़खल झील गुलजार हो सकती है और यहां पहुंचने वाले पर्यटक झील को पानी से भरा पाएंगे. जिसमें एसटीपी प्लांट के तहत फरीदाबाद का वेस्ट पानी झील में ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा जाएगा और इससे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा।

all pages:20 JAN Page 1.qxd 6/30/2023 2:46 AM Page 6

पेज 1 का शेष

मलिहाबाद विधान सभा का एक-एक सदस्य मेरे परिवार का हिस्सा है : जय देवी

जवाब: सुबह छह बजे तक अपना घरेलू काम निपटाने के बाद हम आम के पेड़ के नीचे कुर्सी खिंचकर बईठ जाते हैं ताकि बारी-बारी से सबकी समस्या सुनकर दो मिनट में फैसला सुना सकें। ये भीड़ जो आप देख रहे हो हमरे परिवार के लोग हैं। हम इनकी समस्या नहीं निपटा पायेंगे तो बेकार है विधायक होने का...। आखिर हमका विधायक यही लोग तो बनाये हैं,फिर हमरे रहते यदि क्षेत्र के लोग परेशान हो तो क्या फायदा...।

सवाल: किस तरह के मामले आते हैं?

जवाब: गांव में जमीन के पट्टों का विवाद,घरेलू विवाद,महिलाओं का विवाद और सबसे अधिक लड़के-लड़कियों की शादी का मामला आता है। मैं दोनों परिवार को पास बुलाती हूं और प्यार से समझा देती हूं कि जब लड़का-लड़की शादी के लिये तैयार हैं तो आपलोग आशीर्वाद दे देओ ताकि इनलोगों का घर खुशहाल बन सके। मेरे समझाने पर बहुत घर बस गये हैं। इसी तरह,पुलिस-थाने के प्रकरण आते हैं कि शिकायत करने के बाद भी दारोगा काम नहीं कर रहा है,तो फोन कर मामले को सुलटा देते हैं।

सवाल: आपके पास जितने फरियादी आते हैं क्या उनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत हो जाता है या फिर लंबा समय लगता है?

जवाब : देखिये... जिस अधिकारी से संबंधित मामले होते हैं,उसे फोन कर दो मिनट में मामलों का निस्तारण कराते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मेरे दरवाजे जो आये,खुश होकर जाये। आप जब कभी आयेंगे आपको यहां पर समस्या लेकर आने वालों की भीड़ नजर आयेगी लेकिन जाते समय सभी खुश होकर जाते हैं। जब कोई परेशान हो तो उम्मीद के साथ हमारे पास आता है और उसकी समस्याओं को दूर करा देते हैं तो लोग दुआ ही देकर जाते हैं।

सवाल: आपके पति कौशल किशोर सांसद हैं,आप विधायक, पत्नी और मां हैं। तीनों रोल कैसे अदा करती हैं,कैसे सामंजस्य बनाकर रखती हैं?

जवाब : जिस तरह मैं पत्नी और मां का काम पूरे मन से करती हूं,ठीक उसी तरह अपने दरवाजे आने वालों की समस्याओं को भी अपना समझ कर दूर करने का भरसक प्रयास करती हूं। कौशल जी की पहचान देश-प्रदेश में अपनी ईमानदारी और काम की वजह से होती है। सुबह उठने के बाद नाश्ते के टेबल पर हमलोगों की बातें होती है। नाश्ता में उन्हें एक आम,कीवि,सेब लेते हैं। इस दौरान राजनीति की कम और परिवार की बातें होती है। उस दौरान सांसद जी को हल्का-फुल्का नाश्ता देने के बाद हमदोनों फरियादियों की समस्याओं को निपटाने में लग जाते हैं।

सवाल : कौशल जी पहले की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ दिखते हैं। दिन-रात काम का दबाव रहता है उसके बाद भी आप इन्हें फीट कैसे रखती हैं?

जवाब : देखिये,कौशल जी अब केन्द्रीय मंत्री हैं तो स्वाभाविक है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गयी है। काम के बोझ के बीच भी वे समय के बहुत पाबंद हैं। यदि लखनऊ में हैं तो कुछ भी हो जाये एक बजे घर आ जाते हैं या फिर उनका टिफिन समय पर उन तक पहुंच जाता है। खाने में तरोई की सब्जी,चावल या मखाना लेते हैं। कहीं बैठक में होते हैं तो बिना तेल के मखाना ज्यादा भेज देते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि वे खाते कम बांटते ज्यादा हैं...।

सवाल: आप कौशल जी का सेहत बनाने की बात कर रही हैं लेकिन नाश्ता-खाने में इतनी कंजूसी क्यों करती हैं?

जवाब: अरे भईया,देख रहे हो आपके सांसद जी पहले से कितने फीट हैं। हैं कि नहीं बताओ...। पेट बिल्कुल अंदर हो गया है...। एकदम नौजवान की तरह दिखने लगे हैं और ये सब समय पर कम खाना खाने की वजह से हुआ है। आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना अधिक काम करेंगे। वैसे भी कौशल जी पर जिम्मेदारियां बहुत है।

सवाल: आप दोनों के पास फरियादी आते हैं। क्या कभी आपको सांसद जी के पास आने वाले केस को भी निपटाना पड़ा?

जवाब: अरे,यहां तो हर दिन सांसद जी के कई प्रकरण को निपटाती हूं। लोग क्षेत्रीय समस्या लेकर जाते हैं तो वे सीधे मेरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। चूंकि हम दोनों सुबह होते ही जनता की फरियाद सुनने बैठ जाते हैं तो सभी मामले आसानी से निपट जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि रात के समय भी लोग अपनी बात लेकर चले आते हैं तो हमलोग ये नहीं देखते की दिन है या रात...

सवाल: आपकी शादी 1984 में हुयी। कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप बताना चाहती हो?

जवाब: भईया,हमरी शादी में एक नहीं कई मजेदार बातें हुयी। आपलोगों को शायद नहीं मालूम की कौशल किशोर जी मुझे देखने के लिये हमारे गांव बहादुर आये थे,जो गुडम्बा थाना के पास है। मेरे पिता जी बैजू प्रधान जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा। जब से प्रधान बनें आखिरी सांस तक वही प्रधान रहें। पिता जी की हनक थी और कौशल किशोर जी मुझे देखने आये। हमका मालूम नाही रहा कि कोई लड़का देखे आवा है। हम सिर पर आंचल डालकर घर के सामने बने कुंआ से पानी भर रहे थे। कुछ दूर पर लगे बेर के पेड़ के नीचे सांसद जी सफेद बेलबाटम पहने,अमिताभ बच्चन की तरह बड़े-बड़े बाल रखे मुझ घूर रहे थे। उनके साथ एक दोस्त भी था। हमका का मालूम हम रस्सी से खींचकर बाल्टी पानी निकाले और बल्टी में भर कर अंदर चले गये। कौशल जी को हम पसंद आ गये थे लेकिन उनके परममित्र ने कान में फूंक दिया कि लड़की सुंदर तो है लेकिन आंखें भूरी है...देख लेओ सही नाही होत है...। फिर क्या था,सांसद जी को परम मित्र की बातें सही लागी और एक साल तक मामला ठंडा रहा। एक साल बाद कौशल जी को समझ में आया कि लड़की संस्कारी और सुंदर है,शादी तो जया से ही करेंगे। हमरे घर आये सबसे मिले लेकिन हमलोग तैयार नहीं थे। भईया का भरोसा...पहले कहें आंख भूरी है और शादी बाद कुछ हो जाये तो...। उस समय मेरी शांति दीदी पुलिस इंस्पेक्टर थी। उन्होंने बात की और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद हमलोगों की 23 अप्रैल 1984 को शादी हुयी।

सवाल : शादी के दिन कौशल किशोर जी बारात लेकर गांव पहुंचे,उस समय की कोई रोचक बातें,जो बताने लायक हो?

जवाब: सवाल सुन विधायक जया देवी हंस पड़ी और बताया कि कौशल जी टेम्पू में बैठकर और बाराती ट्रैक्टर पर लदकर हिचकोले खाते हुये हमरे गांव पहुंचे। इंटरव्यू के दौरान सांसद कौशल किशोर जी भी पहुंच गये...। शादी के दौरान की बातों के बीच उन्होंने बताया कि जब हमलोगों की शादी हो रही थी तो दूल्हे के हांथ में पीले रंग का धागा बांधा जाता है,जिसे मैंने निकाल कर जेब में रख लिया था और पंडित जी के बगल में खड़ा हो गया। पंडित जी आवाज लगा रहे थे कि अरे,शादी में देर हो रही है दूल्हा कहां है? इस पर जब मैंने कहा कि पंडित जी दूल्हा मैं हूं... तो वे चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। सांसद जी की बातें सुन वहां मौजूद लोगों ने जोरदार ठहाका लगाया।

सवाल : यानि,शादी ठीक तरीके से हो गयी और आप जया कौशल किशोर बनकर अपने ससुराल आ गयीं?

जवाब: अरे नहीं,अभी आगे की सुनो...। शादी का रस्म तो पूरा हो रहा था तभी लड़के वालों ने कहा कि कल सुबह कौशल जी को परीक्षा देने जाना है इसलिये सुबह का रस्म आने के बाद होगा। सुबह भात खिलाने और विदाई की रस्म रोक दी गयी। कौशल जी देर शाम वापस लौट कर आये तब जाकर भात खिलाने का रस्म पूरा हुआ। सच्चाई ये थी कि जिस दिन हमारी विदाई थी कौशल जी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में अपना नामांकन भरने गये थे। लौटने के बाद रात में मेरी विदाई हुयी और हम आ गये अपने ससुराल।

सवाल: उस वक्त कौशल किशोर जी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आपलोगों ने कैसे स्थिति को संभाला,क्या बताना चाहेंगी?

जवाब : जिस जगह पर आप बैठे हैं,यहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक कच्ची कोठरी और एक छप्पर था। कौशल जी गरीब जरुर थे लेकिन शुरु से मैंने देखा ईमानदारी और खुद्दारी उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी। ईश्वर की कृपा रही कि उस वक्त भी हमारे दरवाजे पर कोई परेशान होकर आता था तो कौशल जी उसकी मदद के लिये तैयार हो जाते थे। भूखा आता तो घर में जो रूखा-सूखा होता,उसे भी खिलाते थे। वो संघर्ष का दिन था,जिसमें हमलोग खूब तपे...। आर्थिक स्थिति इतनी तंगहाल थी कि कई बार मेरे बच्चे दूध देख नहीं पाते थे। पानी में भिगोंकर पारले बिस्किट खिलाती थी। मेरे तीन बच्चे हैं जो गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाये लेकिन संस्कारवान बनाया।

सवाल : जो गर्दीश का दौर देखता है वही आगे चलकर इतिहास रचता है। आप दोनों पति-पत्नी राजनीति से लेकर सामाजिक स्तर पर एक बड़ा नाम बन गये हैं। अब कैसा लगता है? सांसद जी के साथ जब बैठती हैं तो किन मुद्दो पर खूब बातें होती है?

जवाब : गर्दीश के दौर में तो सूखे सावन,भरे बादल वाला मौसम था। बैठकर तो आज भी बातें नहीं हो पाती। यदि होती भी है तो थोड़ी देर बाद वो तकरार में बदल जाती है। शादी में हमदोनों ने सात फेरे लिये हैं उनमें से एक फेरा राजनीति का है...।

all pages:20 JAN Page 1.qxd 6/30/2023 2:46 AM Page 7

जंग के बीच पुतिन को एक दिन में लगे 2 बड़े झटके, अब बेलारूस के राष्ट्रपति ने छोड़ा देश

रूस के मौजूदा हालात कब बदल जाएंगे कोई नहीं जानता। रूस में ये हालात क्यों बने हैं कोई नहीं जानता. लेकिन दुनिया को इतना तो पता है कि अब रूस किसी भी वक्त विद्रोह की आग में झुलस सकता है।

यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस को एक दिन दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ तो रूस के भाड़े के सैनिक कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया है तो वहीं दूसरी बड़ी खबर बेलारूस से आ रहा है। जहां यूक्रेन के खिलाफ रूस ने मोर्चाबंदी करके रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक, बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुशेंको ने देश छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक, लुशेंको के परिवार का जेट बीती देर रात उड़ता हुआ दिखाई दिया। बेलारूस की दूरी यूरोप से ज्यादा नहीं

है। बताया जा रहा है कि क्रेमलिन से लुशेंको की पहले ही तल्खी हो चुकी थी. उसी का ये नतीजा माना जा रहा है।

रूस में तेजी से हालात बदल रहे हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ ने राष्ट्रपति पुतिन को सीधी धमकी तख्तापलट की दी है। जाहिर है ये पहला मौका है जब पुतिन को सीधा चैलेंज मिला है। वहीं अब तो ये भी खबर आ रही है कि मॉस्को की तरफ वैगनर के लड़ाकों ने कूच कर दिया है और वैगनर ग्रुप की दहशत के चलते बेलारूस के राष्ट्रपति ने मुल्क छोड़ दिया है. हालांकि, अभी ये खबर सूत्रों के हवाले से है।

पुतिन के भरोसेमंद ने दिया धोखा-विद्रोह के ये हालात किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन के उस भरोसेमंद ने पैदा किए हैं जो किसी जमाने में सड़क पर हॉटडॉग बेचा करता था और देखते ही देखते पुतिन का बेहद करीबी बन गया. शनिवार का सवेरा रूस के लिए तख्तापलट की आहट लेकर आ गया। रूस के वैगनर ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन पर तख्तापलट की साजिश का आरोप लगा है।

रूसी हेलिकॉप्टर गिराने का दावा-गौरतलब है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए मॉस्को हाई-अलर्ट पर है। मॉस्को को दूसरे शहरों से जोड़ने वाले तमाम हाईवे को बंद किया गया है। प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनके लड़ाके रूसी सीमा में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने रूस की सेना के एक हेलिकॉप्टर को भी मार गिराया है. राष्ट्रपति पुतिन को तमाम घटनाओं से जुड़ी सारी जानकारी दी जा रही है।

पेज 1 शेष

मुख्यमंत्री के ट्रांसफर पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रमुख सचिव!

बहरहाल,सचिवालय में बैठे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं आखिर क्या सोचकर ये लोग अपने चहेतों को कुर्सी खाली करने के लिये नहीं कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चिराग तले अंधेरा कहावत चरितार्थ हो रहा है। तबादला नीति आने के बाद सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मंथन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तबादला नीति में कहीं चूक ना हो जाये। नियम के तहत समयावधि पूरी करने वालों का ही तबादला हो ताकि उन पर कोई सवाल ना उठा सके। वहीं,सचिवालय प्रशासन में नियमों को ताख पर रखकर अनुभाग अधिकारी,संयुक्त सचिव,उप सचिव व अनु सचिव लंबे समय से एक ही कुर्सी पर बैठ कर मलाई खा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें करने वाली सरकार की नीतियों पर सचिवालय प्रशासन के तथाकथित अधिकारी ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। 10 फरवरी 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में निति का निर्धारण किया गया है।

अपर मुख्य सचिव एन.एस.रवि द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि प्रस्तर संख्या 1 में संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के किसी अधिकारी व कर्मचारी को उनके संपूर्ण सेवाकाल में किसी एक विभाग में तैनाती की अधिकतम अवधि में संशोधन किया गया है। समूह क में अनु सचिव,उप सचिव का स्थानांतरण नीति पूर्व में 5 वर्ष था,जिसे नवीन निर्धारित समयावधि में 3 वर्ष किया जाता है। संयुक्त सचिव,विशेष सचिव का पूर्व में 3 वर्ष था जो इस समय भी 3 वर्ष ही रखा गया है। इसी तरह,समूह ख में समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी व समकक्ष का पूर्व में 7 वर्ष समयावधि था जिसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। समूह ग में कम्प्यूटर सहायक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व समकक्ष का पूर्व में 10 वर्ष का समयावधि था जिसे घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया है।

किशलय सिंह तो एक बानगी हैं। सचिवालय प्रशासन के विभिन्न अनुभागों में आठ से दस सालों से अनगिनत अनुभाग अधिकारी,संयुक्त सचिव,अनु सचिव तैनात हैं। एक सीट पर लंबे समय से तैनात होने की वजह से यदि जांच करायी जाये तो अधिसंख्य करोड़पति निकलेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उनका तबादला नहीं होगा लेकिन महत्वपूर्ण सीट पर होने की वजह से वे दूसरों का तबादला कर लाखों का वारा-न्यारा जरूर करते रहेंगे।

हास्यापद तो यह है कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के तबादला नीति पर सही ढंग से पालन करने के लिये अधिकारी माथा-पच्ची कर रहे हैं कि कहीं कोई उन पर ऊंगली ना उठा दे और सचिवालय प्रशासन में...। ना छापने की शर्त पर वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के. रविन्द्रनायक ही जब मुख्यमंत्री के तबादला नीति की अनदेखी कर रहे हैं तो कैसे मान लिया जाये कि अन्य विभागों में तबादला नीति का पालन किया जायेगा। बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री की नीतियों को अवहेलना कर अपने चहेतों को बचाने वाले अधिकारियों पर गाज गिरेगी या फिर...।

अफ्रीकी-यूरोपीय बाजारों में बढ़ेगी भारत की पैठ, वैश्विक-दक्षिण की आवाज बनने का भी मौका

भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय मिस्र का दौरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत इस उत्तरी-अफ्रीकी देश में निवेश बढ़ा सकता है और इसे ब्रिक्स में शामिल करवाने में मदद भी कर सकता है। दूसरी ओर, भारत को भी वैश्विक-दक्षिण में मजबूत आवाज बनने के साथ अफ्रीका, अरब एवं यूरोप के बाजारों में पैठ और गहरी करने के लिये एक और दरवाजा मिलने की उम्मीद है। दौरा कई मायनों में दोनों देशों के लिए अहम् है।

मोदी के दौरे के बीच मिस्र के साथ मुक्त व्यापार समझौते, एफटीए की मांग उठी है। विशेषज्ञों की मानें तो इस देश में कृषि व इस्पात उत्पादों और हल्के वाहन जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग के लिये बड़ी संभावनाएं हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि भारत व मिस्र के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंध हैं, जो मजबूत व काफी संतुलित हैं। मिस्र अफ्रीका व यूरोप का प्रवेश द्वार है। कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि, नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के अलावा भारत को मिस्र के साथ लॉजिस्टिक्स में साझेदारी की संभावनाएं तलाशनी चाहिये। सहाय ने यह भी कहा है कि हमें मिस्र के साथ व्यापार को आगामी तीन वर्षों में 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 15 अरब डॉलर करने की जरूरत है।

मिस्र को इस दौरे से पश्चिमी ब्लॉक के अलावा अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध पुख्ता करने का मौका मिल रहा है। भारत से होने वाला निवेश और ब्रिक्स की सदस्यता तो उसके ध्यान में है ही। मिस्र ने कुछ वर्षों में फिलिस्तीन, इथियोपिया और कुछ अन्य अफ्रीकी देशों के मामलों में अपना दबदबा गंवाया है। यही वजह है कि वह इसे फिर से मजबूत करना चाहता है। भारत से संबंध बढ़ाकर उसे यह मजबूती हासिल हो सकती है। क्षेत्रीय मामलों के अलावा अब मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप से बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व बढ़ाने के रास्ते देख रहा है। इसमें भी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती छवि से उसे मदद मिल सकती है। भारत काहिरा के रास्ते अरब और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में अपनी पैठ गहरी करना चाहता है। जेएनयू में मिडिल-ईस्ट स्टडीज पढ़ा रहे आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि दोनों देश ऐतिहासिक रूप से मित्र रहे हैं। खाड़ी सहयोग परिषद से पीएम मोदी को सीमित सफलता की उम्मीद हैए इसलिए भी मिस्र का रुख करना जरूरी है। मिस्र के ब्रिक्स में आने से भारत भी चीन के सामने संतुलन साध सकेगाए जो इसमें पाकिस्तान को शामिल करने पर तुला है। अरब और अफ्रीकी देशों में मिस्र सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहां मौजूद स्वेज नहर से दुनिया का 12 फीसदी कारोबार होता है। काहिरा से अफ्रीका और यूरोप के बड़े बाजारों का दरवाजा भारत के लिये खुल सकता है।भारत मिस्र से उर्वरक, कच्चा तेल, रसायन, कच्चा कपास और कच्ची खालों का आयात करता है वहीं, गेहूं, चावल, सूती धागा, पेट्रोलियम, मांस, फ्लैट-रोल्ड उत्पाद, फेरोलॉयल,लोहे से संबंधित और हल्के वाहन का निर्यात करता है।

बता दें कि बतौर पीएम यह नरेंद्र मोदी का पहला मिस्र दौरा है। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम यहां आये। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार, पीएम मोदी पारस्परिक दौरे पर मिस्र गये हैं ताकि न केवल दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों की गति बनी रहे, बल्कि उन्हें ऐसी उम्मीद और विश्वास है कि ये रिश्ते अब कारोबार और आर्थिक संबंधों के नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी मिस्र में मौजूद भारतीय समुदाय और देश के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया अमेरिका और सोवियत रूस के दो धड़ों में बंट रही थी, भारत और मिस्र ने मिलकर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। दुनिया के इस शक्तिशाली धड़े से 120 विकासशील देश जुड़े। मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी तीन बार भारत आ चुके हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी नई दिल्ली के मेहमान बने थे। यह सम्मान पाने वाले वह मिस्र के पहले राष्ट्रपति हैं।

पुतिन की प्रशासनिक क्षमता पर उठे सवालय नाखुश लोगों के लिए बन सकता है अवसर

रूस में निजी सेना वैगनर के लड़ाके संक्षिप्त विद्रोह के चलते मॉस्को की सड़कों पर उतरे सरकारी सैनिक वापस अपनी बैरकों में लौट गये हैं। इस विद्रोह ने हालांकि रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के ताकतवर व अजेय होने के मिथक को तोड़ दिया है और इसने यूक्रेन में जंग छेड़ने की उनकी क्षमता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। भाड़े के सैनिकों के कुछ घंटों की बगावत पुतिन के लिये दीर्घकालिक परिणाम साबित हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पहले भी विद्रोह झेल चुके पुतिन इससे और मजबूत होकर उभर सकते हैं।

वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन के नेतृत्व में विद्रोही लड़ाकों का मॉस्को की ओर मार्च शनिवार देर रात बेलारूस के राष्ट्रपति की मध्यस्थता के चलते थम गया। इस विद्रोह ने पुतिन के ऐसे नेता के रूप में ख्याति को गंभीर नुकसान पहुंचाया जो अपने अधिकारों को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बेरहमी से दंडित करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही यह घटना उन लोगों के लिए भी अवसर प्रदान कर सकती है जो सत्ता पर पुतिन की दो दशक की पकड़ से नाखुश हैं। खासकर यूक्रेन पर रूस के हमले के चलते। समझौतों की शर्तों के तहत प्रिगोझिन निर्वासन में बेलारूस जायेंगे और उन्हें आपराधिक मामलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उनके लड़ाकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

वैगनर सैनिकों ने रोस्तोव शहर पर बिना किसी संघर्ष के कब्जा कर लिया था। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में लोगों को वैगनर सैनिकों के पक्ष में नारेबाजी करते और हाथ मिलते देख जा सकता है। इससे पता चलता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जनता के बीच लोकप्रियता घट रही है। इस बीच रीजनल गवर्नर ने कहा कि वैगनर के सभी लड़ाके शहर से जा चुके हैं। रूसी सेना और बागी निजी सेना वैगनर में तय नजर आ रहे खूनी संघर्ष को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ग्रेगरिविच लुकाशेंको ने नाटकीय ढंग से रोक दिया। लुकाशेंको ने वैगनर के प्रमुख येवगेनी वी. प्रिगोझिन से अपनी 20 साल पुरानी दोस्ती का सहारा लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी खत्म करने और बेलारूस आने के लिए मनाया। एक समय मॉस्को की सड़कों पर तैनात टैंकों और वैगनर लड़ाकों के आक्रामक रुख को देखते हुए रूस में भीषण गृहयुद्ध की आशंका नजर आ रही थी। पुतिन सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि लुकाशेंको ने खुद मध्यस्थता की पेशकश की। दिमित्री ने कहाए आप हमसे पूछेंगे कि लुकाशेंको को इससे क्या मतलब? वे क्यों मध्यस्थता करने आ गएघ् बात यह है कि वे येवगेनी को 20 साल से निजी तौर पर जानते हैं।

रूस रूस के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भाड़े के सैनिकों के वैगनर समूह के विद्रोह के बाद घरेलू हालात को स्थिर करने के प्रयासों में चीन ने रूस के नेतृत्व के प्रति समर्थन जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के घटनाक्रम को असाधारण करार दिया। उन्होंने कहा कि 16 महीने पहले पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की तैयारी में थे और अब उन्हें अपने शिष्य के नेतृत्व वाली सेना से ही मॉस्को की रक्षा करनी पड़ी। विद्रोह के सुलझने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। रूस में कई दरारें नजर आने लगीं हैं। दिमित्री ने कहा कि 24 जून बेहद मुश्किल दिन था। कई त्रासद घटनाएं हो रही थीं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक संपादक दिव्या श्रीवास्तव गोल्डन लाइन प्रेस 510/115, न्यू हैदराबाद, फूलवाला पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता है। कार्यालय पता- 1288/89 अंसल आंगन आशियाना, लखनऊ। ई मेल-sanjaysrivastava.ss26@gmail.com, मोबाइल नंबर-8317011531, सभी प्रकाशित लेख की जिम्मेदारी संबंधित संवाददाता की होगी। किसी भी लेख से स्वामी, मुद्रक, संपादक से कोई मतलब नहीं होगा। पीआरबी एक्ट के तहत इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवम संपादन हेतु उत्तरदाई तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ के अधीन होंगे। RNI No. UPHIN/2014/58463

all pages:20 JAN Page 1.qxd 6/30/2023 2:46 AM Page 8

लखनऊ कंट्रक्शन की एमडी अलका शुक्ला ने महिला सशक्तिकरण के तहत कीर्ति श्रीवास्तव का किया सम्मान

लखनऊ कन्ट्रक्शन का अवार्ड फंक्शन: कर्मयोगियों को मिला सम्मान

लखनऊ। राजधानी में खूबसूरत मकान बनवाने का शौख रखने वालों के लिये तेजी से लोकप्रिय नाम बन चुके लखनऊ कंट्रक्शन ने शनिवार को राजधानी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में अपने कर्मयोगियों को सम्मानित किया। अपने काम के दम पर लखनऊ कंट्रेक्शन लगातार चार साल से अवार्ड फंक्श ान करता चला आ रहा है। इस बार लखनऊ कंट्रक्श ान की एमडी अलका शुक्ला और फाउंडर मनोज शुक्ला ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर कीर्ति श्रीवास्तव को सम्मानित किया। इनके पति की अकस्मात मृत्यु हो गयी लेकिन अपने दोनों बेटों को अपने दम पर पढ़ा-लिखाकर इस काबिल बनाया कि एक बेटे का चयन भाभा ऍटामिक रिसर्च सेंटर में हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ व्यापार मंडल के चीफ प्रेसिडेंट, सेक्टर वार्डन सिविल डिफेंस एवं राष्ट्रपति पदक विजेता अमरनाथ मिश्रा, डॉ.राघवेन्द्र शुक्ला-पीआरओ, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, महामंत्री-गोमतीनगर जन कल्याण समिति, संजय पुरबिया-स्टेट हेड, द संडे व्यूज़ एवं कृष्ण शंकर त्रिपाठी-अध्यक्ष व्यापार मंडल, विभूति खण्ड गोमतीनगर उपस्थित थे।

The name is enough...
KANCHAN
Sweets & Pastries

लखनऊ में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली
बंगाली मिठाइयों का स्वाद लें और
अपने दिन को यादगार बनाएं

+91 7080090198

Neelgiri Complex, Faizabad Rd, A-Block, Indira Nagar, Lucknow